वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) यद्यपि कई विशेष स्थानों पर विशेष प्रकार के धागे की आवश्यकता और मांग में संतुलन नहीं हुआ होगा लेकिन हथकरघा क्षेत्र में कच्चे माल की कोई कमी नहीं है।

(ख) राज्य हथकरघा अभिकरण जैसे शीर्ष समितियां, राज्य हथकरघा विकास निगम और प्राथमिक समितियां हथकरघा बुनकरों को सूत सप्लाई करती है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम भी इन प्रयासों में अपना योगदान देता है। सूत प्राइवेट व्यापारियों तथा मास्टर बुनकरों को भी दिया जाता है।

(ग) प्लेन रील हैंक यार्न पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता जबकि क्रोस रील हैंक यार्न पर रियायती दर से शुल्क लिया जाता है। सूत के शुल्कों में हाल ही की बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने एक समय अल्पावधिक उपाय के रूप में रियायती शुल्कों में हैंक यार्न की सीमित मात्रा की सप्लाई करने की एक योजना तैयार की है।

(घ) ऐसी कई रिपोर्ट मिली हैं कि क्रोस रील हैंक यार्न पावरलूम द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।

(ङ) क्रोस रील हैंक यार्न पर रियायती उत्पाद शुल्क के दुरुपयोग से बचने के लिए रियायत केवल हथकरघा अभिकरणों द्वारा सूत की खरीद पर ही उपलब्ध होती है।

वस्त्र व्यापार पर सीमा शुल्क समाप्त किया जाना/कम किया जाना

5561. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री अनन्त राम जायसवाल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और यूरोपीय संघ भारत से कपड़ा व्यापार में सीमा शुल्क को समाप्त करने/उसकी दर को कम करने के लिए भारत पर दबाव डाल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अमरीका की क्या मांग है और क्या सरकार ने अब तक इस पर कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार इस मामले में क्या करना चाहती है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) बाजार में प्रवेश दिलाने सम्बन्धी उरुग्वे दौर की वार्ताओं के एक भाग के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों ही भारत से आग्रह करते रहे हैं कि वह वस्त्रों और क्लोदिंग मदों के अपने शुल्कों को उस स्तर पर बन्धित करे जिन स्तरों पर वे वास्तविक रूप से व्यापार होने की संभाव्यता की दृष्टि से उचित तथा उपयुक्त समझते हैं। भारत संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूरोपीय संघ दोनों से ही स्वतः यह प्रयास कर रहा है कि वे उसके वस्त्र तथा क्लोदिंग उत्पादों के लिए अपने बाजार में प्रवेश पाने के बेहतर अवसर प्रदान करें। भारत को पारम्परिक संतोषजनक समाधान ढूंढने की दृष्टि से वस्त्र क्षेत्र में बाजार में प्रवेश दिलाने के मुद्दे पर संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ के साथ और वार्ताएं करनी है।

Nationalisation of Sick Textiles Mills

5562. **SHRI KRISHAN LAL SHARMA:** Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to nationalise fifteen sick textile mills;

(b) if so, the reasons of their nationalisation instead of privatising them;

(c) the liability of each of these mills; and

(d) the future plans in respect of sick textile mills ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (d) The modernisation/rationalisation plans prepared by the Textile Research Associations for the revival of NTC mills have been endorsed by the Special Tripartite Committee. The Special Tripartite Committee on the NTC has also unanimously recommended nationalisation of the taken over mills. A statement indicating the liability of each of these 15 mills is enclosed (*See* below). These plans shall require the approval of Board for Industrial and Financial Reconstruction under the provisions of the Sick Industrial Companies (Special Provision) Act, 1985 after it is approved by the Govt. before they can be implemented.

Statement

Liabilities of Non-Nationalised Mills as on 31-12-1993

S. No.	Name of the Mills	Amount (Rs. in crores)